***Date*:** 29-09-2020
***Publication*:** Prabhat Khabar
***Edition*:** Dhanbad

कोल इंडिया ने कोयले से मेथेनॉल बनाने को ग्लोबल टेंडर जारी किया

एजेंसियां ▷ नयी दिल्ली

कोल इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने कोयले से मेथेनॉल बनाने के संयंत्र लगाने को लेकर वैश्विक बोलियां आमंत्रित की है. प्रस्तावित संयंत्र के लिए पश्चिम बंगाल में दानकुनी कोल काम्प्लेक्स (डीसीसी) को परियोजना स्थल के रूप में पहचान की गयी है. यह कारखाना बनाओ-अपनाओ-चलाओ (बीओओ) मॉडल पर आधारित होगा. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह सरकार के मेथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था कार्यक्रम के क्रियान्वयन का हिस्सा है. इसका मकसद देश के आयात बिल में कमी लाना है. संयंत्र के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया गया है. बीओओ परिचालक संयंत्र का डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उत्पादन और भंडारण के अलावा उसे पट्टे पर भी दे सकेंगे. कोल इंडिया प्रस्तावित संयंत्र के लिए जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध करायेगी. संयंत्र से सालाना 6.76 लाख टन मेथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य है. इसका उपयोग पेट्रोल में 15 प्रतिशत तक मिश्रण में किया जायेगा. संयंत्र पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड और बिहार की जरूरतों को पूरा करेगा. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है.

कॉमर्शियल माइनिंग के लिए 278 निविदा दस्तावेज बिके

सरकार ने सोमवार को कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग के तहत नीलामी के लिए रखे गये कोयला ब्लॉक को लेकर संभावित बोलीदाताओं ने 278 निविदा दस्तावेज खरीदे हैं. सरकार ने कॉमर्शियल माइनिंग के लिए 38 कोयला खानों को नीलामी के लिए रखा है. कोयला मंत्रालय ने कहा, संबंधित प्राधिकरण 29 सितंबर दो बजे तक बोली दस्तावेज प्राप्त करेंगे. बोलियों को 30 सितंबर सुबह 10 बजे खोला जायेगा. कोयला मंत्रालय ने नीलामी के लिए रखे गये कोयला खदानों की सूची को संशोधित कर 41 से 38 कर दिया है.

***Date*:** 30-09-2020
***Publication*:** Hindustan Hindi
***Edition*:** Dhanbad

कोयले के ई-ऑक्शन में अब 'कोरोना राहत' खत्म

धनबाद | विशेष संवाददाता

कोरोना काल में कोयले के ई-ऑक्शन में दी गई राहत अब खत्म कर दी गई है। कोल इंडिया ने सभी अनुषंगी कंपनियों को बाजार की स्थिति के अनुसार नोटिफाइड प्राइस पर प्रीमियम लगा रिजर्व प्राइस तय करने की अनुमति दे दी है। सीआईएल बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है। यानी अब अप्रैल 2020 के पहले की तरह कोयले का ई-ऑक्शन होगा। कोरोना के कारण कोयले के ई-ऑक्शन में अप्रैल से सितंबर तक के लिए नोटिफाइड प्राइस और रिजर्व प्राइस को एक रखा गया था। केंद्र सरकार की पहल पर यह राहत दी गई थी। तब कोल कंपनियों के पास कोयला का काफी स्टॉक था और मांग कम थी। कोयले की मांग बढ़ाने एवं कोयला स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए सभी तरह के ई-ऑक्शन स्कीम में राहत स्वरूप यह कदम उठाया गया था। मामले को लेकर सभी अनुषंगी कंपनियों को कोल इंडिया के कंपनी सेक्रेटरी एम विश्वनाथन की ओर से अवगत कराया गया है। साथ में लिखा गया है कि इससे संबंधित गाइड लाइन जल्दी जारी होगी।

आदेश जारी

- 1 अक्तूबर से ई-ऑक्शन में अप्रैल के पूर्व की स्थिति होगी बहाल
- अक्तूबर में होने वाले ई-ऑक्शन में नोटिफाइड से 10 प्रतिशत अधिक रिजर्व प्राइस होगा

कोरोनाकाल में भी मिला 9 प्रतिशत प्रीमियम

यूं तो कोरोना कल में कोयले की मांग कम थी। बावजूद इसके ई-ऑक्शन में राहत के बावजूद कोयले को नोटिफाइड प्राइस पर औसतन नौ प्रतिशत प्रीमियम मिला। जानकार बताते हैं कि इससे से उत्साहित हो कोल इंडिया ने राहत को खत्म करने का निर्णय लिया है। जब कोरोना काल में नौ प्रतिशत प्रीमियम मिला तो अब कोयले की मांग पहले से बेहतर हुई है। इसलिए अनुषंगी कंपनियों को बाजार के अनुरूप रिजर्व प्राइस तय करने की अनुमति दे दी गई है।

***Date*:** 01-10-2020
***Publication*:** Sanmarg
***Edition*:** Asansol

कोल इंडिया ने अनुषंगी कंपनियों को रिजर्व प्राइस तय करने की अनुमति दी

सांकतोड़िया : कोरोना काल में कोयले के ई-ऑक्शन में दी गई राहत अब खत्म कर दी गई है। कोल इंडिया ने सभी अनुषंगी कंपनियों को बाजार की स्थिति के अनुसार नोटिफाइड प्राइस पर प्रीमियम लगा रिजर्व प्राइस तय करने की अनुमति दे दी है। सीआईएल बोर्ड ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। यानी अब अप्रैल 2020 के पहले की तरह कोयले का ई-ऑक्शन होगा। मालूम हो कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कोयले के ई-ऑक्शन में अप्रैल से सितंबर तक के लिए नोटिफाइड प्राइस और रिजर्व प्राइस को एक रखा गया था। केंद्र सरकार की पहल पर यह राहत दी गई थी तब कोल कंपनियों के पास कोयला का काफी स्टॉक था और मांग कम थी। कोयले की मांग बढ़ाने एवं कोयला स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए सभी तरह के ई-ऑक्शन स्कीम में राहत स्वरूप यह कदम उठाया गया था। मामले को लेकर सभी अनुषंगी कंपनियों को कोल इंडिया के कंपनी सेक्रेटरी एम विश्वनाथन की ओर से अवगत करा दिया गया है। साथ ही लिखा गया है कि इससे संबंधित गाइड लाइन जल्दी जारी की जाएगी।

कोरोनाकाल में भी मिला 9 प्रतिशत प्रीमियम : यूं तो कोरोना काल में कोयले की मांग कम थी। बावजूद इसके ई-ऑक्शन में राहत के बावजूद कोयले को नोटिफाइड प्राइस पर औसतन नौ प्रतिशत प्रीमियम मिला। जानकार बताते हैं कि इससे से उत्साहित हो कोल इंडिया ने राहत को खत्म करने का निर्णय लिया है।

***Date*:** 02-10-2020

***Publication*:** The Pioneer
***Edition*:** Ranchi

CIL scripts record growth in output, off-take in Sept 2020 and Q2 FY'21

Ranchi: Scripting a new high Coal India Limited (CIL) recorded the highest ever growth in production and off-take, for any month of September so far, by clocking 31.6 per cent and 31.7 per cent respectively. For the first time in the current fiscal growth was in double digits in both the facets with all CIL's subsidiaries turning out growth. Supplies to power and non-power sector consumers and rake loading also registered high level growth.

Coal production at 40.51 MTs in September'20, surged ahead by a robust 9.73 MTs increase in absolute terms, compared to 30.78 MTs in September'19, the growth being 31.6per cent. Among CIL's subsidiaries the top three leading the growth trend were Mahanadi Coalfields Limited (MCL) with 68.5 per cent followed by Central Coalfields Limited (CCL) 47.4per cent and Western Coalfields Limited (WCL) 43.7per cent.

"Now that we broke the growth jinx in output and off-take, which were weighed down by the pandemic induced slowdown, we expect to better our performance in the ensuing months. We aim to reclaim as much of the lost ground as possible during the rest of the fiscal" said a senior official of the company, adding, "generally the H2 performance is higher in terms of production and supplies".

CIL's coal off-take saw a sizeable jump of 11.2 MTs during the referred month. CIL supplied 46.46 MTs in September'20 against 35.28 MTs same month last year logging a growth of 31.7 per cent. MCL again registered the highest growth among the subsidiaries with 63 per cent followed by WCL 60.2per cent and CCL 31.5 per cent.

Supplies to non-power sector logged a growth of 65 per cent in September'20 at 10.04 MTs compared to 6.08 MTs in September' 19. Coal despatch of 36.42 MTs to Power Sector during the month witnessed a growth of 24.7per cent compared to 29.20 MTs as of September'19, the increase in absolute terms being 7.2 MTs.

CIL on an average loaded a total of 241.2 rakes per day in September'20 against 162.2 rakes same month last year recording an increase of 79rakes per day with a growth of around 49per cent. Loading to non-power sector doubled to 31.2 rakes per day during the month compared to 15.4 rakes of last year's September. Loading to Power sector bagged a growth of nearly 43per cent at 210 rakes per day against 147 rakes for the comparable period.

"Despite Covid related challenges and inclement monsoon our production increased by 11 MTs and off-take by 12 MTs during the second quarter of the present fiscal" said the stated official. CIL produced 115 MTs of coal for the July-September'20 period against 104 MTs same quarter last year logging a growth of 10.6per cent. CIL supplied 134.4 MTs of coal during current year's Q2 compared to 122.4 MTs same quarter last year registering a growth close to 10per cent.

Supplies to coal fired power utilities during current year's Q2 at 103.2 MTs also logged a growth of around 3per cent. CIL supplied 100.29 MTs during same quarter last fiscal. ***PNS***

***Date*:** 02-10-2020
***Publication*:** The Financial Express
***Edition*:** Bengaluru

CIL records growth in Q2 despite Covid constraints

FE BUREAU
Kolkata, October 1

PSU MINER COAL India (CIL) recorded positive growth in the second quarter of the current fiscal despite operational constraints due to the Covid-19 pandemic and a heavy monsoon.

CIL's production increased by 11 million tonne, with 115 million tonne (MT) of coal produced from July to September, as against 104 MT during the same period last fiscal.

Offtake increased by 12 MT during the second quarter, with supplies at 134.4 MT as against 122.4 MT during the corresponding period last fiscal.

It registered around 10% year-on-year growth in both production and offtake.

Supplies to coal-fired utilities during the second quarter of the current fiscal were at 103 MT, and registered y-o-y growth of around 3%.

Average loading in the second quarter was at 224.6 rakes per day, registering a 23.6% growth compared to 182 rakes loaded in the same quarter last fiscal.

Loading for the power sector clocked a 16% y-o-y growth at 189.7 rakes a day.

The growth was mainly driven by September's production and offtake, which grew 31.6% and 31.7%, with 40.51 MT produced and 46.46 MT supplied, respectively.

Among CIL's subsidiaries, the top three that drove the growth were Mahanadi Coalfields (MCL) with 68.5% y-o-y growth, followed by Central Coalfields (CCL) with 47.4% and Western Coalfields (WCL) 43.7% y-o-y growth. Even in terms of offtake, MCL registered the highest growth with 63%, followed by WCL at 60.2% and CCL at 31.5%.

Loading to the non-power sector doubled to 31 rakes per day compared to 15.4 rakes last September, while that for the power sector grew about 43% at 210 rakes per day as against 147 rakes in the comparable period

September supplies to the non-power sector clocked a 65% y-o-y growth with despatches at 10.04 MT.

Coal despatch to the power sector was at 36.42 MT during the month, witnessing a 24.7% y-o-y growth.

In September, CIL loaded an average 241.2 rakes per day as against 162.2 rakes in the same month during the last fiscal.

Loading to the non-power sector doubled to 31 rakes per day compared to 15.4 rakes last September, while that for the power sector grew about 43% at 210 rakes per day as against 147 rakes in the comparable period.

***Publication*:** The Economic Times

***Date*:** 05-10-2020
***Edition*:** Kolkata

CIL Allocation to Power Cos Under Forward E-auction Up 8% in Apr-Aug

Press Trust of India

New Delhi: CIL's coal allocation under special forward e-auction for the power sector registered a rise of 8.4% to 7.94 million tonnes (MT) in April-August period of the ongoing fiscal.

The state-owned company had allocated 7.32 MT of dry fuel in the corresponding period of the previous fiscal year, according to the monthly summary by the coal ministry for the Cabinet.

However, in August there was no coal allocation under the scheme, Coal India Ltd (CIL) said. In August 2019-20, 0.62 MT coal was allocated to the power sector by the company, it said.

Coal distribution through forward e-auction is aimed at providing access to coal for such consumers who wish to have an assured supply over a long period, say one year, through e-auction mode so as to plan their operation.

The purpose of the scheme is to provide equal opportunities to all intending coal consumers to purchase coal for own consumption through single window services as per requirement and at a price determined by themselves through the process of online bidding.

Forward e-auction is aimed at facilitating all the consumers of coal across the country with wide ranging choice for booking coal online, enabling them to buy dry fuel through a simple, transparent and consumer friendly system of marketing of the fossil fuel.

CIL is one of the major suppliers of coal to the power sector. The company, which accounts for over 80 per cent of domestic coal output, is eyeing 710 MT output in 2020-21.

The PSU is eyeing one billion tonne of output by 2023-24.

The company will pump over Rs 1.22 lakh crore in projects related to coal evacuation, exploration and clean coal technologies by 2023-24, to achieve 1 billion tonne of fuel output target, Coal Minister Pralhad Joshi had said.